try offences arising out of violation of human rights. It is upto the State Governments to decide as to the need for setting up of Human Rights Courts, with the concurrence of the High Courts.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

जल संसाधनों का उपयोग

1768. **श्री अजीत जोगी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े और मध्यम बांधों के माध्यम से जल संसाधनों का उपयोग करने की वर्तमान प्रणाली समुचित ढंग से कार्य नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार सिंचाई हेतु अन्य सस्ते विकल्पों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (घ) देश में जल संसाधन विकास में वर्तमान नीति विकल्पों के मिश्रण पर आधारित है जिसमें बड़े, मध्यम और लघु सतही जल भण्डारण तथा व्यपवर्तन परियोजनाएं, सरकारी क्षेत्र में गहरे नलकूपों के जरिए भूजल विकास तथा निजी/सहकारी क्षेत्र में उथले नलकूप/खुले कुएं, परिस्रवण टैंकों (परकोलेशन टैंक) सहित लघु पैमाने पर सतही भंडारण तथा माइक्रो जल विभाजक विकास स्कीमें शामिल हैं। भंडारण जलाशय, भूजल विकास और जल विभाजक (वॉटरशेड) विकास प्रत्येक का अपना स्थान है और सभी विकल्पों के न्यायोचित मिश्रण से ही देश में जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो सकेगा।

विखंडनीय समाग्री के उत्पादन पर एक पक्षीय प्रतिबंध

1769. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरीका तथा अन्य देशों की विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर एक पक्षीय प्रतिबंध के संबंध में भारत के दृष्टिकोण से अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस निर्णय की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) से (ग) सरकार का यह मानना है कि एक ऐसी संधि एक विशिष्ट समय-सीमा के भीतर सभी नाभिकीय हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के उद्देश्य को लेकर बनाए गए चरणबद्ध सार्वभौमिक नाभिकीय निरस्त्रीकरण दृष्टिकोण का अंग होनी चाहिए जो बहुपक्षीय आधार पर की गई बातचीत के माध्यम से सम्पन्न की गई हो; सार्वभौमिक आधार पर लागू हो और भेदभाव-रहित हो तथा जो नाभिकीय शस्त्र प्रयोजन के लिए विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाती हो। सरकार ऐसा कोई सुझाव स्वीकार नहीं कर सकती कि भारत अपनी ओर से इस संबंध में कोई प्रतिबंध लगाए। सरकार इस संबंध में एक सिद्धान्तगत तथा सुसंगत नीति पर चलती रही।

राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार हेतु विदेशी सहायता

1770. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार हेतु परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु वर्ष 1995 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते के अंतर्गत अब तक कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई है तथा मरम्मत किए जाने वाले राजमार्गों के नाम क्या-क्या हैं एवं उन देशों के नाम क्या-क्या हैं, जिनसे यह सहायता प्राप्त हुई है; और

(घ) जिन अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को इस समझौते के अंतर्गत लाने हेतु कार्यवाही की गई है, उनके नाम क्या-क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी०जी० वेंकटरामन): (क) से (ग) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2, 5, 8 और 24 के सुधार के लिए वर्ष 1995 के दौरान एशियाई विकास बैंक के साथ 245 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के एक ऋण समझौते, ओवरसीज इकोनामिक को-आपरेशन फंड (ओ ई सी एफ) के अंतर्गत जापान सरकार के साथ 10663

मिलियन जापानी येन की राशि के दो ऋण समझौतों और जापान सरकार से 2830 मिलियन जापानी येन के सहायता अनुदान पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Loss to Navy due to failure of Missile Protection System

1771. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether some of the missile protection systems and electronic warfare programme bought by the Navy tor over Rs. 50 crore, failed during sea acceptance trials and had to be upgraded compromising the Navy's operational requirements;

(b) whether the matter has been enquired into, responsibility fixed and action taken against the authorities responsible for endangering the security of the Nation and wasteful expenditure; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) Some systems had partially failed during the initial sea acceptance trials but these were suitably modified by the firm for the Navy's use without compromising operational requirements.

(b) and (c) A special audit by CDA (Navy) has been ordered into the deficiencies in the implementation of the contract pertaining to the Electronic Warfare Systems.

Ncwsitcm, Telephone Lines have miles to go

1772. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem which appeared in the Hindustan Times dated the 6th July, 1996 under caption "Telephone lines have miles to go";

(b) if so, the details in this regard; and

(c) the steps taken in the matter?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The gap between the demand and supply of telephone over the years has drastically reduced. In the first tour years of 8th Plan additional capacity of 61.68 lakh lines has been created tor reducing the waiting list drastically. In fact barring a few pockets, the OYT connections are current. To accelerate the momentum of providing telephones to all villages, Government under National Telephone Policy 1994 has allowed participation by private operators to provide value added services and basic services.

Development of Telecom Network on such a massive scale involves installation of exchanges and heavy cable laying. In Delhi two lakh subscribers have been given connections during 1995-96. Only in a few places the release of connections was delayed due to non availability of cable pairs. In such cases prompt action is taken to solve the problems by using pair gain system. Release of connections arc reviewed at the higher level and continuous efforts arc made to improve the services.

There arc 603906 villages in the country out of which 216632 have been provided with public telephone facility.

Calcutta Telephone district has 468 villages out of which 56 have been provided with public telephone facility upto 31.3.96. Tamil Nadu has 20196 villages out of which 14430 have been covered with public telephone facility. The remaining villages are being covered progressively.